(b) and (c) The State Government's Annual Plan 1995-96 was finalised at Rs. 3157.00 crores. At the time of finalisation there was a resources gap of Rs. 1,000 crores. The State Government mobilised Rs. 250 crores as additional resoruce which left a gap of -Rs. 750.00 crores. Planning Commission had visualised that this gap of Rs. 750.00 crores would be met from the Award of the Tenth Finance Commission. The State Government already received Rs. 846.00 crores as per the Award of the Tenth Finance Commission.

(d) The question does not arise.

आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आर्थिक विकास दर

3345. **श्री चीमनभाई हरिभाई शुक्ला:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के सभी वर्षों के दौरान कुल औसत आर्थिक विकास दर प्राप्त कर ली गई है;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य में औसत आर्थिक विकास दर कितनी-कितनी थी;

(ग) उद्योग और अन्य सेवा क्षेत्रों में उच्च राष्ट्रीय विकास का क्या प्रभाव रहा; और

(घ) उपर्युक्त अवधि के दौरान उक्त दोनों क्षेत्रों में राज्य-वार कितनी औसत विकास दर दर्ज की गयी है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) से (घ) 1993-94 से 1996-97 तक चार वर्षों में से प्रत्येक वर्ष में प्राप्त की गई वार्षिक विकास दरें आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि (1992-93—1996-97) के लिए लक्ष्य के रूप में निर्धारित 5.6 प्रतिशत वार्षिक औसत आर्थिक विकास दर से अधिक रही हैं। उच्च वार्षिक विकास दरों का उद्योग और अन्य सेवाओं पर प्रभाव पड़ा जिससे सकल घरेलू उत्पाद (जी डी पी) में उद्योग और अन्य सेवाओं का हिस्सा आधार वर्ष (1991-92) के 70 प्रतिशत से बढ़कर आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष (1996-97) में 74 प्रतिशत हो गया। प्रत्येक राज्य संघ राज्य क्षेत्र में औसत कुल आर्थिक विकास दर तथा उद्योग और अन्य सेवाओं के क्षेत्र में औसत विकास दर को विवरण में दर्शाया गया है। **(नीचे देखिए)**

विवरण

आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 1980-81 की कीमतों पर निवल राज्य घरेलू उत्पाद (एनएसडीपी) की राज्यवार विकास दर

क्र०सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आठवीं पंचवर्षीय योजना का औसत विकास दर		
		कुल एएसडीपी	उद्योग क्षेत्रक	सेवाएं क्षेत्रक
1.	आन्ध्र प्रदेश	5.4	3.71	7.47
2.	अरुणाचल प्रदेश	3.0	7.24	5.91
3.	असम	2.8	4.94	3.21
4.	बिहार	0.4	—0.07	2.73
5.	गोवा	7.6	7.11	8.83
6.	गुजरात	12.1	17.45	7.35
7.	हरियाणा	4.7	5.78	5.21
8.	हिमाचल प्रदेश	5.3	8.82	4.58
9.	जम्मू और कश्मीर	4.4	5.07	4.93
10.	कर्नाटक	4.7	4.97	5.99
11.	केरल	6.7	6.90	7.94
12.	मध्य प्रदेश	6.1	8.66	4.71

क्र०सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आठवीं पंचवर्षीय योजना का औसत विकास दर		
		कुल एएसडीपी	उद्योग क्षेत्रक	सेवाएं क्षेत्रक
13.	महाराष्ट्र	9.6	9.25	9.34
14.	मणिपुर	4 4	2.23	6.16
15.	मेघालय	3.8	2.92	4.76
16.	नागालैण्ड	8.0	22.91	3.61
17.	उड़ीसा	2.7	7.09	4.70
18.	पंजाब	4.7	9.29	3.57
19.	राजस्थान	7.8	5.57	6.82
20.	सिक्किम	0.0	0.00	0.00
21.	तमिलनाडु	6.0	6.89	7.54
22.	त्रिपुरा	8.0	9.94	11.86
23.	उत्तर प्रदेश	3.4	3.52	3.81
24.	पश्चिम बंगाल	6.7	5.55	7.53
25.	अण्डमान और निकोबार द्वीप	14.1	115.59	14.56
26.	दिल्ली	4.8	7.51	4.60
27.	पांडिचरी	2.2	0.09	5.59

टिप्पणी:—

1. एनएसडीपी के राज्य अनुमान संबंधित अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय द्वारा तैयार किए जाते हैं।
2. प्रयुक्त स्रोत सामग्री में विभिन्नता के कारण विभिन्न राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के आंकड़े पूर्णतः तुलनीय नहीं हैं।
3. मिजोरम राज्य इन अनुमानों को केवल वर्तमान कीमतों के आधार पर तैयार करता है।
4. चंडीगढ़, दादर और नगर हवेली, दमन और द्वीव तथा लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र इन अनुमानों को तैयार नहीं करते हैं।
5. उद्योग क्षेत्रक में खनन और उत्खनन, विनिर्माण, निर्माण और विद्युत, गैस और जल आपूर्ति शामिल है।
6. अवशिष्ट क्षेत्रक में शामिल सेवाएं (उपर्युक्त वर्णित (I) उद्योग क्षेत्रक एवं (II) वानिकी एवं मछली पालन सहित कृषि क्षेत्रक के अलावा)

Non-completion of projects

3346. SHRI BHAGABAN MAJHI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the details of the schemes monitored by the Planning Commission which have not been completed as per schedule during 1997-98;

(b) the number of schemes completed during the above period;

(c) whether Government have found out the reasons for the non-completion of the projects;

(d) if so, the details in this regard; and

(c) the amount of loss suffered by Government as a result thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS, THE MINISTRY OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI RAM NAIK): (a) As on December, 1997, 191 projects were due for completion in 1997-98. The details are given in the Annual Report of the Department of Programme Implementation for the year 1997-98, laid on the table of the House.